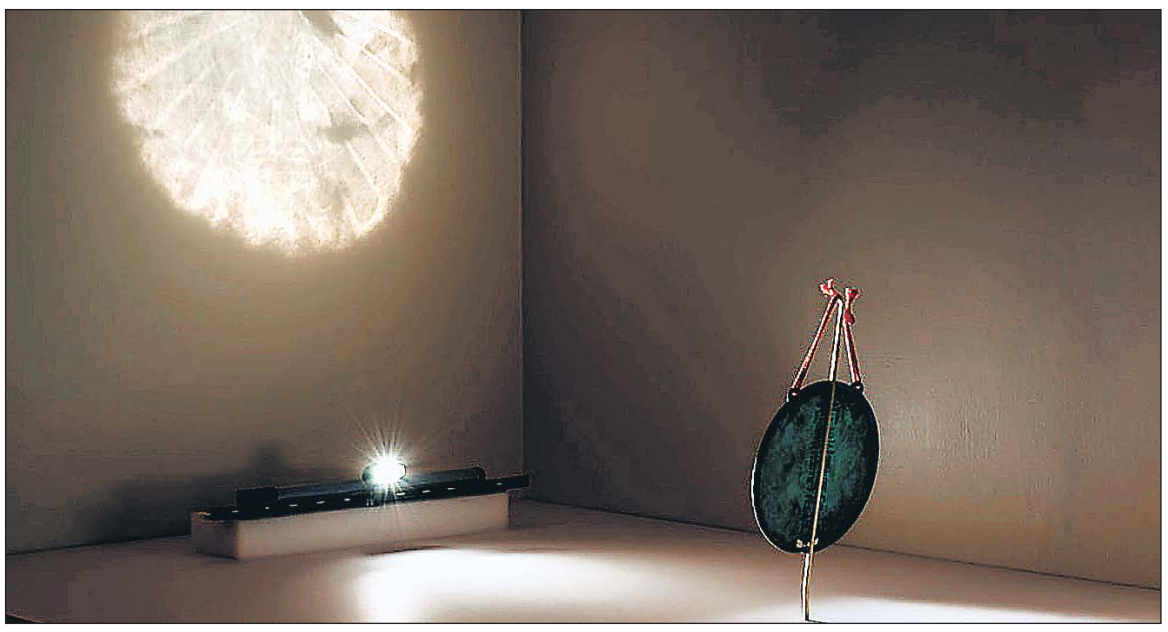

सिनसिनाटी आर्ट म्यूज़ियम में 16 वीं सदी का एक साधारण सा दिखने वाला कांसे का दर्पण है, जिसे प्रकाश की विशेष स्थिति में रखने पर इससे परावर्तित प्रकाश की किरणों से दीवार पर भगवान बुद्ध की छवि बनती है। यह जादूई दर्पण 23 जुलाई 2022 से म्यूज़ियम में सार्वजनिक रुप से प्रदर्शित है। वर्ष 2021 में म्यूज़ियम संग्रह के प्राचीन आर्ट वर्क पर रिसर्च करते हुए ईस्ट एशियन आर्ट के क्यूरेटर डॉ. होऊ-मेई सुंग ने यह खोज की। कांच के निर्माण से पहले लोग पॉलिश किए हुए कांसे से बने आइने में अपना अक्स देखते थे। यह तकनीक प्राचीन मिस्र से लेकर सिंधू घाटी तक हर जगह मिली है। इन दर्पणों को "मैजिक," "ट्रांसपैरेंट" (पारदर्शी) या "लाइट पैनिट्रेटिंग मिरर" के नाम से जाना जाता था। इस प्रकार की कलाकृतियां सबसे पहले चीन में हान साम्राज्य (202 ईसा पूर्व -220 ईस्वी) के दौरान बनाई गई थीं। जब इन आइनों पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, तो ये पारदर्शी लगने लगते हैं और इनपर बनी डिजाइन या अक्षर दिखाई देने लगते हैं। सुंग ने कहा, यह चीन के लिए राष्ट्रीय खजाना है और हम बेहद भाग्यशाली हैं जो इस दुर्लभ कलाकृति को ढूंढ पाए और जो सिनसिनाटी में प्रदर्शित है। यह दर्पण कई दशकों से म्यूज़ियम के ईस्ट एशियन संग्रह में रखा था, सदियों से जिसे किसी ने छुआ नहीं था। म्यूज़ियम के दर्पण के अग्र भाग को पॉलिश किया हुआ है, जिससे प्रकाश परावर्तित होता है। इसके पीछे छः चाइनीज़ अक्षरों में "अमिताभ बुद्ध" लिखा है। प्राचीन मैजिक मिरर का निर्माण बहुत कठिन है और ये बहुत दुर्लभ हैं। शंघाई म्यूज़ियम के हान साम्राज्य के मैजिक मिरर्स के अलावा इस तरह के दो और बौद्ध मैजिक मिरर्स के बारे में जानकारी है। एक टोक्यो नैशनल म्यूज़ियम में और दूसरा मैट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम ऑफ आर्ट में। ये दोनों जापानी मिरर हैं जो एडो काल (1603-1867) में बने थे। सुंग का मत है कि सिनसिनाटी में जो मिरर है वह प्राचीन चीन में बना था। हालांकि यह मिरर कैसे काम करता है यह तो समझ में आ गया पर उस काल में कारीगरों ने लाइट पैनिट्रेशन का इफैक्ट कैसे हासिल किया, यह पता नहीं है।

आनंद शर्मा, हुड्डा और पृथ्वीराज चव्हाण ने दिल्ली में आज़ाद से मुलाकात की

तीनों नेताओं ने इसे शिष्टाचार भेंट बताया है, लेकिन माना जा रहा है कि, आने वाले समय में कांग्रेस के बागी नेता पार्टी के लिए और बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं

- **गौरतलब है कि, पिछले दिनों आनंद शर्मा ने भी कड़ा तेवर दिखाते हुये उनकी अनदेखी किये जाने का आरोप लगाते हुये हिमाचल प्रदेश कांग्रेस चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था।**

नई दिल्ली, 31 अगस्त। कांग्रेस का बागी जी-23 समूह पार्टी के लिए आने वाले दिनों में और बड़ी मुश्किलें खड़ी करेगा , अब यह बात तय हो गयी है। बीते सप्ताह वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ दी थी, लेकिन अब यह आग बढ़ती दिख रही है। मंगलवार को पार्टी के सीनियर नेता आनंद शर्मा, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा और पृथ्वीराज चव्हाण ने गुलाम नबी आजाद से दिल्ली में मुलाकात की।

जी-23 या ग्रुप ऑफ 23 कांग्रेस में बागी नेताओं का एक समूह है जो लम्बे समय से कांग्रेस में आमूलचूल परिवर्तन की मांग करता आ रहा है। ये सभी नेता उस जी-23 का हिस्सा हैं, जिन्होंने सोनिया गांधी को पार्टी में सुधार के लिए पत्र लिखा था। उस लेटर के बाद से ही यह नेताओं की पार्टी में अनदेखी हो रही है। पिछले दिनों आनंद शर्मा ने हिमाचल प्रदेश चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि, इन तीनों नेताओं ने मुलाकात के बाद कहा कि, वे गुलाम नबी आजाद के पुराने मित्र हैं और यह मीटिंग औपचारिक थी। लेकिन कयास जरूर लगने शुरु हो गये हैं कि, आने वाले दिनों में कांग्रेस में हलचल और तेज होगी।

दरअसल, हरियाणा में कांग्रेस ने भूपिंदर सिंह हुड्डा को कमान दी है। करीबी उदयभान को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और उनकी विरोधी कही जाने वाली कुमारी शैलजा को पद से हटाया गया है। उसके बाद भी हुड्डा का आजाद के खेमे में रहना कांग्रेस को अलर्ट करने वाला है। इसके अलावा जी-23 का ही हिस्सा कहे जाने वाले शशि थरूर भी अलग ही सुर में दिख रहे हैं। उनका कहना है कि पार्टी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना चाहिए और जितने ज्यादा उम्मीदवार होंगे, उतना ही बेहतर होगा। उनके स्टैंड से यह चर्चा शुरू हो गई है कि वह भी अध्यक्ष पद के चुनाव में उतर सकते हैं। साफ है कि जी-23 समूह पार्टी के अंदर और बाहर दोनों तरफ से मुश्किल बढ़ा रहा है।

गुलाम नबी आजाद से मुलाकात के बाद कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि पार्टी ने अपने रवैये में बदलाव नहीं किया। इसी के चलते आजाद साहब को पार्टी से अलग होने का फैसला लेना पड़ा। इस बीच जी-23 के कुछ और नेता अनौपचारिक मीटिंग कर रहे हैं और जल्दी ही उनकी ओर से भी कुछ ऐलान किया जा सकता है। इन नेताओं के साथ शशि थरूर भी आ सकते हैं, जिनके बारे में चर्चा है कि पार्टी अध्यक्ष के लिए वह चुनाव लड़ सकते हैं। साफ है कि कांग्रेस की मुश्किलें आने वाले दिनों में बागी बढ़ा सकते हैं। यही नहीं गुलाम नबी आजाद ने जो संकट जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस के सामने खड़ा किया है, वैसी ही चुनौती हिमाचल प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में भी सामने आ सकती है।

तृणमूल कांग्रेस ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

संबंधियों के पास 162 परिसम्पत्तियाँ हैं, जो पूरे राज्य में फैली हुई हैं।

स्वयं अणुव्रत की पुत्री के पास करीब 19 सम्पत्तियाँ हैं, जो कोलकाता के श्रेष्ठ इलाकों तथा विभिन्न जिला-मुख्यालयों पर स्थित हैं। इन लोगों में से किसी के पास भी आय के ऐसे स्रोत शायद ही हों, जो उनकी सम्पत्ति के वैध होने के दावों से मेल खाते हों। सी.बी.आई. 37 सम्पत्तियों को भी चिन्हित करने की कोशिश कर रही है, जिन्हें आरोपी आपराधिक गतिविधियों के संचालन के लिये काम में लेते हों।

इस प्रकार के मामलों का रोजाना हो रहा खुलासा मुख्यमंत्री के साथ ही, तृणमूल के उन वरिष्ठ नेताओं के लिये बहुत ही शर्मनाक बात है, जो हर तरफ से आ रहे जाँच संबंधी प्रश्नों का सामना कर रहे हैं।

ममता बनर्जी ने शुरू में तो आरोपियों से अपने हाथ झाड़ लिये थे। उन्होंने स्वयं को तथा पार्टी को पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी से पूरी तरह अलग कर लेने की कोशिश की थी। इसके बाद, जब अणुव्रत मण्डल को सी.बी.आई. ने गिरफ्तार किया, तो उसको बचाने की कोशिश उन्होंने की थी।

पार्थ चटर्जी तथा अणुव्रत मण्डल के प्रति उनके अलग-अलग रूख को लेकर विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। यह बात खुले तौर पर चर्चा में थी कि इन दिनों, पैसा कमाने की उनकी कोशिशों के मामले में, अणुव्रत मण्डल, ममता बनर्जी के ज्यादा करीब था।

तृणमूल कांग्रेस अनियमितताएं करने के मामले में बहुत दुस्साहसी हो गई है तथा उसका मानना है कि राजनैतिक आदेश उन्हें बचा लेगा। लेकिन इस समय, जिस हद तक पैसा बनाने की बात जनता के सामने आ रही है, उससे उनकी सारी गणनाएं गड़बड़ा रही हैं।

कोलकाता में बड़ा आयकर छापा

नई दिल्ली 31 अगस्त (वार्ता)। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में दो प्रमुख रियल एस्टेट समूहों पर की गयी छापेमारी में 250 करोड़ रुपये की अघोषित आय का पता चला है। आयकर विभाग ने आज यहां जारी बयान में बताया कि 18 अगस्त को यह कार्रवाई की गयी। तलाशी अभियान के दौरान, दस्तावेजों और डिजिटल डाटा सहित बड़ी संख्या में आपत्तिजनक सबूत मिले, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। इस दौरान बहीखातों के बाहर नकद लेनदेन और नकदी की रसीदों के सबूत मिले हैं। कई दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक डाटा से शेल कंपनियों के माध्यम से अघोषित पैसे की रूटिंग के संकेत मिले हैं। इसके अलावा, तलाशी के दौरान अघोषित धनराशि के जमीन के अधिग्रहण में इस्तेमाल किए जाने के भी कुछ प्रमाण मिले हैं।

राडिया...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कि उसने सम्पूर्ण राडिया टेप 2012 में ही नष्ट कर दिये थे।

ऐसी प्रबल संभालना है कि यह प्रकरण न्यायमूर्ति डी.वाई. चन्द्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बैंच के समक्ष प्रस्तुत होगा, जिसके अन्य दो जज हैं-न्यायमूर्ति हिमा कोहली तथा पी. श्री नरसिम्हा। इसके अतिरिक्त 2011 में एक्टिविस्ट एडवोकेट प्रशांत भूषण द्वारा एन.जी.ओ. "सैन्टर फॉर पब्लिक इन्ट्रैस्ट लिटिगेशन" (सी.पी.आई. एल.) की ओर से दायर की एक अन्य याचिका भी सूचीबद्ध है, जिसमें टाटा की बात का विरोध करते हुये, नितान्त निजी वार्तालापों के अलावा, पूरे राडियों टेप्स के प्रकाशन की मांग की गई है ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा नागरिकों की निजता का अधिकार सुनिश्चित हो सके।

केन्द्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय कॉरपोरेट लॉबीईस्ट नीरा राडिया के फोन टैप किए थे। उसके बाद से उसने अपना काम बंद कर दिया और किसी को भी नहीं पता कि वह कहां है।

उसके फोन कॉल्स में क्या था कभी पता नहीं चलता पर एक मैगजीन में फोन कॉल्स के कुछ अंश छप गए उसके बाद टाटा ने नागरिक की निजता में मनमानी घुसपैठ को रोकने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। इन अंशों से पता चला। सुरक्षा एजेंसियां नागरिकों की निजता का उल्लंघन कर रही हैं और यह भी पता चला कि कॉरपोरेट बिजनैस किस प्रकार से होता है।

कर्नाटक हाईकोर्ट ने आधी रात को ईदगाह मैदान में गणेश पाण्डाल स्थापित करने की अनुमति दी

कर्नाटक सरकार ने ईदगाह मैदान में स्थापित गणेश पूजा पाण्डालों के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था दी है

- **ताजा घटनाक्रम में अंजुमन इस्लाम समिति ने हुबली के ईदगाह मैदान में उत्सव की अनुमति देने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेशों पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।**
- **गौरतलब है कि मंगलवार को देर रात हुई सुनवाई में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने धारवाड़ नगर आयुक्त के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें शहर के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी उत्सव आयोजित करने की अनुमति दी गई थी।**

बैंगलुरु, 31 अगस्त। कर्नाटक के हुबली ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी समारोह मनाया जा रहा है, दूसरे समुदाय के लोगों ने इस स्थान पर इस तरह के आयोजन के प्रति असंतोष जताया है। आयोजन की अनुमति देने वाले हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।

ताजा घटनाक्रम में अंजुमन इस्लाम ने हुबली के ईदगाह मैदान में उत्सव की अनुमति देने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेशों पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

गौरतलब है कि मंगलवार को देर रात हुई सुनवाई में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने धारवाड़ नगर आयुक्त के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें शहर के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी उत्सव आयोजित करने की अनुमति दी गई थी।

अनुमति दिए जाने के एक दिन बाद हिंदू नेताओं ने बुधवार सुबह हुबली के ईदगाह मैदान में गणेश की मूर्ति भी स्थापित कर दी है। न्यायालय से अनुमति मिलने के कुछ घंटे बाद ईदगाह मैदान में कड़ी सुरक्षा के बीच बुधवार को गणेशोत्सव की शुरुआत की गई। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच श्रीराम सेना प्रमुख प्रमोद मुतालिक ने अपने समर्थकों के साथ भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की और पूजा-अर्चना की।

मुतालिक ने पूजा पंडाल में पत्रकारों से कहा, "कानूनी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए हमने पूजा-अर्चना की। कुछ असामाजिक तत्वों ने हमें रोकने की कोशिश, लेकिन फिर भी हमने पूजा की जो न केवल हुबली के लोगों के लिए बल्कि पूरे उत्तरी कर्नाटक के लिए खुशी की बात है।" मुतालिक ने कहा कि हिंदू समुदाय लंबे समय से इसका सपना देख रहा था, जिसे उन्होंने एक "ऐतिहासिक" क्षण बताया। मुतालिक के अनुसार, जिला प्रशासन ने तीन दिन तक यहां पूजा करने की इजाजत दे दी है। ईदगाह मैदान में किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं।

रुस के राष्ट्रपति रहे मिखाइल गोर्बाचेव का मंगलवार देर रात 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे 1985 में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने थे। उसके बाद उन्होंने ग्लासनोस्त (खुलेपन) और पेरेस्त्रोइका (पुनर्रचना) की नीतियां लागू कीं, जिनसे शीत युद्ध खत्म होने का रास्ता तैयार हुआ। उन्हें अपनी जिंदगी के आखिर 31 सालों में दोहरे अनुभव हुए। वॉशिंगटन, पेरिस और लंदन में उनकी वाहवाही हुई पर रुस में उनकी भारी आलोचना हुई। वर्ष 1990 में उन्हें शांति का नोबल पुरस्कार मिला था।

कश्मीर के 5 हजार कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर आज़ाद को समर्थन देंगे

गुलामनबी आज़ाद खेमे ने यह दावा किया

- **आज़ाद के जाने से जम्मू-कश्मीर कांग्रेस में बड़ा बिखराव साफ नज़र आने लगा है**
- **अब तक कश्मीर कांग्रेस 100 से ज्यादा रसूखदार नेता गुलामनबी आज़ाद के साथ जुड़ चुके हैं।**
- **बुधवार को आप पार्टी के 51 नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने भी गुलामनबी आजाद को अपना समर्थन दे दिया।**

नई दिल्ली, 31 अगस्त। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी को अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर की राजनीति में बड़ा रसूख रखने वाले आजाद के कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक सप्ताह से भी कम वक्त में कांग्रेस के 100 से ज्यादा नेता पार्टी छोड़कर आजाद को अपना समर्थन दे चुके हैं। बुधवार को जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के 51 नेताओं ने भी पार्टी छोड़कर आजाद को अपना समर्थन दिया है। इतना ही नहीं गुरुवार को कांग्रेस के 5000 कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर आजाद को अपना समर्थन देंगे।

गुलाम नबी आजाद ने बीते 26 अगस्त को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे को कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपने बयानों से यह साबित करने की कोशिश की कि पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन, जिस तरह आजाद के जाने से कांग्रेस पार्टी में बिखराव शुरू हुआ है, खासकर जम्मू कश्मीर में। पहले से देश की राजनीति में अपनी जमीन खो चुकी कांग्रेस के लिए यह किसी बुरे स्वप्न से कम नहीं है।

मिरर नाउ की रिपोर्ट के अनुसार, गुलाम नबी आजाद के समर्थन में जम्मू कश्मीर के 5000 कांग्रेसी कार्यकर्ता गुरुवार को उरी में होने वाले एक कार्यक्रम के दौरान सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे और आजाद को अपना समर्थन देंगे। इससे पहले बुधवार को 42 कांग्रेसी नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दिया और कहा कि वे आजाद की होने वाली पार्टी के साथ जुड़ेंगे।

भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उपयोग आर्थिक वृद्धि को आगे और बढ़ाने में पर्याप्त नहीं होगा क्योंकि बेरोजगारी उच्च स्तर है और वास्तविक वेतन रिकॉर्ड निम्न स्तर पर है।" उन्होंने कहा कि "निवेश के जरिए आर्थिक वृद्धि का समर्थन कर सरकार ने सिर्फ एक ही तरीके पर भरोसा जताया है, जबकि वह उस प्रोत्साहन के बारे में भूल गई है जो घरेलू उपभोग उपलब्ध करवा सकता है। इसीलिए भारत की आर्थिक वृद्धि अब भी वैश्विक महामारी पूर्व से नीचे के ट्रैण्ड पर है।

अर्थव्यवस्था में पर्याप्त मात्रा में इतनी तीव्र वृद्धि नहीं हुई है कि वो कामगारों की फौज में प्रत्येक वर्ष शामिल होने वाले करीब 12 मिलियन लोगों को समायोजित कर सके।

इस बीच रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया (आर.बी.आई.), जो कि वैश्विक कड़े प्रतिबंधों के मामले में अपेक्षाकृत सुस्त है, महंगाई को एक सहनशीलता के दायरे में लाने के प्रयास के तहत मार्च माह के अंत तक अपनी प्रमुख रेपो रेट को 60 बेसिस पॉइन्ट्स और बढ़ा सकता है। इससे पहले इस वर्ष ब्याज दरों में कुल 140 बेसिस पॉइन्ट्स की कुल तीन वृद्धि हो चुकी है और मार्च की वृद्धि के बाद रेपो रेट वर्ष 2023 की प्रथम तिमाही की समाप्ति तक 6.00 प्रतिशत हो जाएगी।

हालांकि केन्द्रीय बैंक का टार्गेट बैण्ड 2 से 6 प्रतिशत है, फिर भी महंगाई के वर्तमान और अगली तिमाही में क्रमशः औसतन 6.9 प्रतिशत और 6.2 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। लेकिन वर्ष 2023 की प्रथम तिमाही में यह 5.8 प्रतिशत की रेंज में रह सकती है।

डी.बी.एस. की सीनियर इकोनॉमिस्ट राधिका राव कहती हैं कि "कीमतों के दबाव में कुछ समय के लिए विराम आ जाने के बावजूद भू राजनीतिक जोखिमों और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की कठिन लैण्डिंग रिस्क्स से उपजी विचारणीय अनिश्चितताओं को देखते हुए महंगाई को हल्के में लेना जल्दबाजी होगा।

कमजोर रूपए के कारण भी अर्थव्यवस्था महंगाई के दबाव में है। भारतीय रूपया अमेरिकी डॉलर की तुलना में करीब 80 रूपए के आसपास ट्रेड करता रहा है। रिज़र्व बैंक डॉलर के भण्डारों को करेंसी मार्केट्स में बेचकर यह स्तर बनाकर रूपए की साख बचाई जा रही है।

रॉयटर के नवीनतम सर्वेक्षण में यह भी दर्शाया गया कि भारत का करेन्ट अकाउन्ट घाटा इस वर्ष बढ़ कर सकल घरेलू उत्पाद का 3.1 प्रतिशत हो गया है जो पिछले एक दशक में सर्वाधिक है तथा इससे करेंसी मार्केट में रूपए पर और दबाव पड़ सकता है।

'चाहे मैं ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

चाहिए कि ऐसे परिणाम क्यों आए ? क्योंकि पहली बार कई सालों में ऐसा हुआ है कि, युनिवर्सिटी चुनाव में एनएसयूआई चुनाव नहीं जीत सकी। युवा देश के आने वाले भविष्य की उम्मीद हैं। उनकी सोच के अनुसार प्रदेश के संगठन और सरकार को काम करना चाहिए।

दालें 8...

.(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रु. का वित्तीय भार पड़ेगा।

ये दालें उस भंडार से दी जा रही हैं जो प्राइस सपोर्ट स्कीम तथा प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड के तहत खरीदा गया था। राज्यों को यह पेशकश इसलिये की गई है ताकि वे कल्याणकारी योजनाओं के तहत इनका उपयोग कर सके, जिनमें इसके साथ उपलब्ध 30.55 टन की पी.डी.एस. भी शामिल है। केन्द्र ने कहा है कि आगामी रबी की फसल में दालों की अच्छी पैदावार की उम्मीद है। 2022-23 के दौरान मिनिमम सपोर्ट प्राइस (एम.एस.सी.) पहले से ज्यादा रखा गया है।

सरकारी सूत्रों का कहना है कि किसानों को दालों की लाभकारी कीमत मिलेगी, जिससे वे इनकी खेती में और ज्यादा निवेश करके, दालें उगाने के लिये प्रेरित -प्रोत्साहित हों।

सूत्रों ने कहा कि इससे देश को दालों के मामले में आत्म-निर्भर होने में मदद मिलेगी।

के.सी.आर. बिहार में और केजरीवाल...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

किन्हीं भी अच्छे एवं उपयोगी विचारों, जो जनता के लाभ एवं हित में हैं, को किसी से भी ग्रहण करने में संकोच नहीं करते हैं।

अभी जब स्टालिन दिल्ली गये थे तो वहां से उन्होंने दिल्ली सरकार द्वारा संचालित स्कूलों के पीछे निहित विचार को समझा। उन्होंने यह भी देखा कि ये स्कूल कैसे संचालित किये जा रहे हैं। और उन्होंने तमिलनाडू में ऐसा ही करने का विचार बना लिया।

यही कारण है कि उन्होंने केजरीवाल को तमिलनाडू में आमंत्रित किया है ताकि वे राज्य सरकार के शैक्षिक प्रयासों को देखें, जिससे तमिलनाडू के स्कूली शिक्षा तंत्र को और बेहतर बनाया जा सके। स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने के लिये उन्हें केजरीवाल से बेहतर व्यक्ति कौन मिल सकता है जिनके सरकारी स्कूल शिक्षा कार्यक्रम की खुली प्रशंसा न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने मुख पृष्ठ पर प्रकाशित की हो।

5 सितम्बर, शिक्षक दिवस को, केजरीवाल स्टालिन के साथ 26 स्कूल्स ऑफ एक्सीलैंस तथा 15 मॉडल स्कूलों का उद्घाटन करेंगे। पुतुमाई पैन पिट्टम (बालिकाओं के लिये नवाचार प्रोजैक्ट), 26 स्कूल ऑफ एक्सीलैंस तथा 15 मॉडल स्कूलों, जो पूरे राज्य में फैले हुये हैं, के उद्घाटन के लिये केजरीवाल को आमंत्रित करने के लिये, तमिलनाडू के मुख्यमंत्री ने अपने शिक्षा मंत्री एनबिल महेश को केजरीवाल के आवास पर भेजा है।

एक राजनैतिक विश्लेषक ने कहा है, "जब दो राजनेता मिलते हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उनके बीच राजनीति पर कोई चर्चा न हो। दोनों नेताओं के बीच घनिष्टता पैदा होगी तथा राष्ट्रीय राजनीति पर विचार-विनिमय भी होगा। लेकिन इन मीटिंग में कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं की जा सकती क्योंकि डी.एम.के. का गठबंधन कांग्रेस से है तथा इसलिये इस मुलाकात के बाद भी, कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है।

यह चीज निश्चित रूप से दिलचस्प है कि स्टालिन ने एक ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित किया है, जो इस समय केन्द्र सरकार तथा भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का कोपभाजन है। वस्तुतः स्टालिन अभी तक नीट के विरोध में हैं तथा हाल ही में तमिलनाडू के एक विश्वविद्यालय के समारोह में, उन्होंने प्रधानमंत्री की मौजूदगी में अपना मत पूरी मजबूती रखा था।

हालांकि स्टालिन इस बात को लेकर सजग हैं कि उनकी गिनती टकरारवादियों में न हो तथा वे केन्द्र सरकार तथा प्रधानमंत्री के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध रखते हैं, लेकिन वे किसी अप्रिय बात को चुपचाप सहन करने के आदी नहीं है।

हाँ, जब आर्थिक कामकाज की बात आती है तो उनके वित्त मंत्री पी. त्यागराजन केन्द्र सरकार से टकराने में चूकते नहीं है तथा कई मानदंडों पर केन्द्र की अर्थव्यवस्था के ट्रैक-रिकॉर्ड पर सवाल खड़े करते रहते हैं।

सोनिया...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

चैकअप के लिए दिल्ली से रवाना हुई थीं। उसके बाद वो अपनी बीमार माँ से मिलने गई थीं।

चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत के सकारात्मक जी.डी.पी. आंकड़ों ने चौंकाया

2022-23 की अप्रैल-जून तिमाही में भारत की आर्थिक विकास दर 13.5 प्रतिशत रही

- **पिछले साल अप्रैल-जून तिमाही में भारत की विकास दर 20.1 प्रतिशत रही थी।**
- **अप्रैल-जून तिमाही में भारत को कुल 36.85 लाख करोड़ रु. की आय हुई है।**

नई दिल्ली, 31 अगस्त (वार्ता)। आर्थिक गतिविधियों में सुधार के बीच देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में चालू वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में 13.5 प्रतिशत का उछाल दर्ज किया गया। पिछले वित्त वर्ष 2021-22 की इसी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 20.1 प्रतिशत थी।

पिछले वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में कोविड महामारी की दूसरी लहर ने आर्थिक गतिविधियों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया था।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की बुधवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया है, अनुमान है कि वर्ष 2011-12 कीमतों पर आधारित वास्तविक जीडीपी 2022-23 की पहली तिमाही में 36.85 लाख करोड़ रुपये के स्तर को प्राप्त कर लिया है जो 2021-22 की पहली तिमाही में 32.46 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले 13.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। 2021-22 की पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 20.1 प्रतिशत थी।

वर्ष 2022-23 की पहली में वर्तमान कीमतों पर जीडीपी 64.95 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जबकि 2021-22 में की पहली तिमाही में चालू कीमत पर जीडीपी 51.27 लाख करोड़ रुपये थी।

इस तरह यह वर्तमान कीमतों पर जीडीपी में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 26.7 प्रतिशत की वृद्धि रही। 2021-22 में चालू कीमत पर जीडीपी में 32.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी थी।

एनएसओ के आंकड़ों से पता चलता है कि चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में कृषि क्षेत्र में सालाना आधार पर 4.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि इसी अवधि के दौरान विनिर्माण क्षेत्र में 4.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस अवधि के दौरान खनन क्षेत्र में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। श्रम प्रधान क्षेत्रों में माने जाने वाले निर्माण क्षेत्र में जून तिमाही में सालाना आधार पर 16.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

प्रमुख देशों की कमजोर मांग ने हाल के कुछ महीनों में देश के निर्यात को प्रभावित किया है जबकि मासिक जीएसटी संग्रह, ऑटो बिक्री, बिजली की खपत और हवाई यातायात वृद्धि जैसे जल्दी-जल्दी आने वाले आंकड़े घरेलू मांग में मजबूत बनी रहने का संकेत दे रहे हैं।

बीआर अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के कुलपति एन आर भानुमूर्ति ने इन आंकड़ों पर टिप्पणी करते हुए कहा, पहली तिमाही में आर्थिक वृद्धि 13-15 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान था। कुछ ने इसे 17 प्रतिशत तक रहने का अनुमान लगाया।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34 फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908